

विचार/संवाद

A close-up portrait of a middle-aged man with a warm smile. He has short, light brown hair and is wearing a dark blue, long-sleeved button-down shirt. The background is slightly blurred, showing what appears to be an indoor setting with a brick wall and a window.

पंकज चतुर्वेदी

जानना जरूरी है कि हाथियों
को 100 लीटर पानी और 200
किलो पते, पेड़ की छाल आदि
की खुशक जुटाने के लिए हर
रोज 18 घंटों तक भटकना
पड़ता है। हाथी दिखने में भले
ही भारी-भरकम है, लेकिन
उनका मिजाज नाजुक और
संवेदनशील होता है। थोड़ी
थकान या भूख उसे तोड़ कर
रख देती है। ऐसे में थके
जानवर के प्राकृतिक घर
यानी जंगल को जब नुकसान
पहुंचाया जाता है तो मनुष्य से
उसकी मिडंत होती है।



जानवर क्या किसी वन-उत्पाद खाने से मरेगा तो हड्डबड़ाहट हुई। वन महकमे के अफसर संस्थेंड हुए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली की ओर से मग्र वन विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में हाथियों के विसरा में माइक्रो टॉक्सिन साइक्लोपियाजोनिक एसिड मिलने की पुष्टि हुई है। एपीसीसीएफ और मग्र वन विभाग की आर से गठित एसआइटी के प्रमुख एल कृष्णमूर्ति के मुताबिक, आईवीआरआई ने विसरा सैंपल की विवाक्ता रिपोर्ट से पता चलता है कि हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो पौधे/अनाज खाए थे। हालांकि, विसरा सैंपल में मिला साइक्लोपियाजोनिक एसिड कितना जहरीला था और कितनी मात्रा में था, क्या यही मौत का कारण हो सकता है-इसकी आगे जांच अभी जारी है। दुर्भाग्यरूप है कि मध्य प्रदेश में जंगल और बनोपज आय के बड़े माध्यम हैं, लेकिन बाघ के लिए जम कर खर्च करने वाली सरकार हाथी के लिए लापरवाह रही है। प्रदेश में हाथियों के प्रबंधन के लिए सिर्फ एक करोड़ सालाना का

बजट वन विभाग के पास है। प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रदेश का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच रहता है, लेकिन हाथियों के प्रवंधन पर प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए वन विभाग ने इस साल 66 लाख रुपये रखे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरूआत 1992 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी जो अभी देश के 16 राज्यों में चल रहा है। हाथियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और इनके शिकार को रोकने के लिए शुरू की गई योजना में प्राकृतिक आवासों को सुधारना, हाथी-मानव संघर्ष को नियंत्रित करना सहित कई काम किए जाते हैं लेकिन वन विभाग के पास बजट होता नहीं है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सहेज कर रखने में गजराज की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण-मित्र पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। जगली हाथियों के बस्तियों में घुमने को किसी राज्य की सीमा से बांधा जा नहीं सकता। आंकड़ों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि करीबी राज्य ओडिशा के हालात हाथियों को लेकर इन्हें खराब हैं कि दौरैल और

गुस्सैल हो गए जंगली हाथी छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में अपनी खीज मिटा रहे हैं। इंडियन इस्टिट्यूट ॲफ साइंस, बैंगलुरु के एक अध्ययन में बताया गया था कि ओडिशा में उपलब्ध जंगल और संसाधन में अधिकतम 1700 हाथी भली प्रकार जी सकते हैं, जबकि आज यहां गजराज की संख्या 2100 से अधिक है। इस तरह 400 से अधिक हाथियों के लिए भोजन, पानी और आने पायावर्सीय संकट सामने दिख रहा है। सरकारी रिकार्ड में है कि 2017-18 और 4 नवम्बर, 2024-25, ओडिशा में 634 मारे गए, जिनमें 22 का शिकार हुआ, एक को जहर दिया गया 91 जानबूझकर बिजली के इंटके से, 32 आकर्षिक बिजली करंट से मारे गए। जबकि 28 हाथी रेल से टकरा कर काल के गाल में गए। इसी साल 58 हाथियों की सर्दियाँ मौत हुई, जिसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं।

जानना जरूरी है कि हाथियों को 100 लीटर पानी और 200 किलो पत्ते, पेड़ की छाल आदि की खुराक जुटाने के लिए हर रोज 18 घंटों तक भटकना पड़ता है। हाथी दिखने में भले ही भारी-भरकम हैं, लेकिन उनका मिजाज नाजुक और संवेदनशील होता है। थोड़ी थकान या भूख उसे ताड़ कर रख देती है। ऐसे में थके जानवर के प्राकृतिक घर यानी जंगल को जब नक्सान पहुंचाया जाता है तो मनुष्य से उसकी फिर्भत होती है। 2018 में पेरियार टाइगर कन्जर्वेशन फाउंडेशन ने केरल में हाथियों के हिंसक होने पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन रिपोर्ट में पता चला कि जंगल में पारंपरिक पेड़ों को काट कर उनकी जगह नीलगिरी और बबूल बोने से हाथियों का भोजन समाप्त हुआ और यही उनके गुस्से का कारण बना। पेड़ों की ये किस्म जीवन का पानी भी सोखती हैं, सो हाथी के लिए पानी की कमी भी हुई। पायावरण-मित्र पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान में भी हाथी बेजोड़ हैं। हाथी की उपस्थिति स्वरथ जंगल की निशानी है, अच्छा जंगल धरती पर इंसान के लिए अनिवार्य है। अब सरकार और समाज, दोनों को हाथी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

बाल दिवस पर विशेष : बालश्रम की भट्टी में झुलसता देश का भविष्य..?



राकेश अचल



हैं बालश्रम का यह अवैध धंधा बड़े पैमाने पर पनपता जा रहा है समाज को इस पर मंथन करना होगा। अगर समय रहते इस पर रोक न लगाई तो भविष्य में हालात बेकाबू हो सकते हैं देश में खैनी, जरदा, तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, व अन्य नशीले पदार्थों के उद्योगों में बालश्रमिक ही इन को बनाते हैं। माचिस, आतिशाजी, के उद्योगों में इनका शोषण किया जाता है। इनके मालिक इनको भर पेट खाना तक नहीं खिलाते हैं जिस कारण कई बाल मजदूर बीमार हो जाते हैं और असमय काल का ग्रास बन जाते हैं इनके मालिकों द्वारा इनके स्वास्थ्य की जांच तो दूर की बात है। बाल मजदूरी गरीबी की वजह से पैदा होती है। परिवार पालने के लिए दिन रात काम करते हैं इन बाल मजदूरों को आराम तक का समय भी नहीं मिलता है।

बालश्रम के उन्मूलन के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यह देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। आज बाल मजदूरों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती जा रही हैं मगर सरकारें इस पर रोक लगाने में अक्षम नजर आ रही है प्रतिदिन हजारों बाल मजदूरों को सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से मुक्त करवाया जाता है मगर ऐसे भी मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आ रहे हैं और बालमजदूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं प्रशासन का चाहिए बिना समय गंवाए इस पर त्वरित एकशन लेना चाहिए दिशा में आज बाल श्रमिकों का आंकड़ा कम होने के बजाए बढ़ता जा रहा है। इस पर रोक लगानी होगी। आज नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती बाल मजदूरी की तरफ झोंका जाता है बाल मजदूरों की सुक्ष्मा के लिए काफी कानून बने हैं परं वे नाकामी साखित हो रहे हैं। यदि इन्हे कारगर ढंग से लागू किया जाए तो इस पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। आज यह समस्या विश्व व्यापी बनती जा रही हैं बाल मजदूरी को रोकने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा ताकि इस पर नकेल लग सके और देश का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। समाज को एक ब्रत लेना होगा तभी इस पर लगाम लग सकती है अन्यथा बाल मजदूर बालश्रम की भठ्ठी में झुलसते रहेंगे। बचपन को बचाना होगा। एक अभियान चलाना चाहिए ताकि बाल मजदूरों को मुक्त करवाया जा सके यह देश हित में है बाल मजदूरी की इस प्रथा को जड़ से मिटाना होगा।

१०

प्राथमिकता ए बदलाए

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के तीन महीने बाद भी राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का दौर जारी है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के समर्थन से सत्ता की बागड़ेर संभालने वाले मोहम्मद युनुस प्रभावशाली ढंग से चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता युनुस राजनीति में लोकतात्त्विक और मानवतावादी मूल्यों की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। अंतरिम सरकार का



मर गए। इस घटना का यूनुस न मानवता के विरुद्ध अपराध करार दिया है और हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं दूसरी ओर, हसीना के देश छोड़ते के तीन महीने बाद उनकी पार्टी अवामी लीग एकजुट होने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अवामी लीग ने रविवार को ढाका के नूर हुसैन स्क्वायर पर विरोध मार्च निकालने का आहान किया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकार्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन की शह पर अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की पिटाई की। लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष होता है, उतना ही विपक्ष भी होता है। अगर देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो यूनुस की सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी। अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर हिन्दूओं पर होने वाले अल्पाचार से विश्व समुदाय चीर्त है। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रॉप ने मतदान से पहले दीवाली के अवसर पर कहा था कि 'मैं हिन्दूओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की निदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़-द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है।' जाहिर है कि दुनिया के एक बड़े नेता की इस टिप्पणी से बांग्लादेश और यूनुस की छाव कलंकित हुई है। बांग्लादेश में शांति और राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से न तो लोकतंत्र स्थापित होगा और न देश बचेगा।

ब शक देश आजाद हो चुका है मगर देश का आधार माने जाने वाले बच्चे आज भी बाल मजदूरी की जरीरों से आजाद नहीं हो पाए हैं, बाल मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। बाल श्रम की भट्टी में बचपन झुलस रहा है मगर जनता के मसीहा बेखबर है। 14 नवंबर 2024 को बाल दिवस मनाया जा रहा है मगर ऐसे आयोजन औपचारिकता भर रह गये हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताब, कापी, पैसिल होनी चाहिए वे हाथ जोखिम उठा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं गंती-बलचा चला रहे हैं नन्हे हाथों में छाले आ जाते हैं जब यह मजदूरी करते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत बाल श्रम अवैध घोषित है। मगर कानून फाईलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि जिनके अभी खेलने कूदने के दिन हैं वे ऐसे काम करते हैं कि रुह कांप उठती हैं। बाल श्रम की समस्या हमारे देश में नई नहीं हैं यह समस्या बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है दिशा में बाल मजदूरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है दिशा में समय पर बाल मजदूरों के हजारों मामले प्रकाश में आते रहते हैं दिशा में बाल मजदूरी के आंकड़े चैकने वाले हैं प्रतिदिन कही न कही बाल मजदूरों को रिहा करवाया जाता है। चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों, उद्योगों और घरों में भी 18.18 घटे काम लिए जाने की घटनाएं तो आम हैं ही, इन्हे इसके बदले दिया जाने वाला मेहनतनामा भी कम होता है। प्रतिदिन देश में बाल मजदूरों को रिहा करवाया जाता है। अगर इस पर सख्त कानून बनाया जाए तो यह बाल मजदूरी पर रोक लग सकती है। देश का भविष्य कहलाले वाले इन नौनिहालों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, यह किसी भी सभ्य समाज और कानून में मान्य नहीं होना चाहिए। हर रोज ऐसे

मामले समाचारों की सुखिं यां बनती है ऐसे मामलों को पर कुछ दिन कारबाई होती है उसके बाद वही परिपाटी चलती रहती है बाल मजदूर पिसते रहते हैं जिनमानस को भी बाल मजदूरी के ऐसे मामलों की शिकायत प्रशासन से करनी चाहिए ताकि उनका शोषण रोका जा सके। देश के प्रत्येक राज्य में ऐसे मामले घटित होते रहते हैं। अगर प्रशासन सरकता से इन पर संज्ञा ले तब इस पर रोक लग सकती है कानूनों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। मालिकों को हवालातों में डाला जाए जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं प्रशासन को छोपमारी करके इन बच्चों को छुड़ाना चाहिए। आखिर कब तक बालश्रम कानून की धज्जियां उड़ती रहेंगी। बाल मजदूरी एक कड़वी सच्चाई है इससे सख्त कानून बनाकर इसका खात्मा करना चाहिए। जिनके अभी

खेलने कूदने के दिन हैं वे ऐसे काम करते हैं कि रुक्कं कांप उठती हैं। बाल मजदूरी आज एक बहस का विषय बनता जा रहा है, कानूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है सरकारें भी कानून बनाकर इतिश्री कर लेती हैं यदि शिक्षक जा कसा जाए तो इस पर कुछ हट तक रोब लग सकती है। श्रम विभाग व्यारा भी कभी कभारा छापामारी की जाती है मगर फिर वही सिलसिल चलता रहता है सरकारें मूद्रकर्शक बनी हुई हैं, यारा सरकारों को जरा भी सदमा होता तो इस प्रथा पर जरूर रोक लगाती। यह समस्या विश्वव्यापी है। आज पटाखा फैक्ट्रियों, चूड़ियों के उद्योगों में, गलीचा बानावाले उद्योगों में बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा है दिश में समय पर बाल मजदूरों को सामाजिक संस्थाओं द्वारा छुड़ाया जाता है। उत्तरप्रदेश, राजस्थान तमिलनाडू, गुजरात, आञ्चलिक, हिमाचल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वारा अधिकतर काम बालश्रमिकों के कधों पर

सड़क हादसे: खड़े कर रहे सवालिया निशान

प्रतिशत है। इसके अलावा 54 प्रतिशत मौतें और गंभीर चोटें मुख्य रूप से संवेदनशील वर्गों जैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक और दोपहिया वाहन सवार आदि में देखी जाती हैं। भारत में 5-29 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों और युवा वयस्कों में सड़क दुर्घटना मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। विश्व सड़क सांख्यिकी के अनुसार, 2018 में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या में भारत दुनिया में फहले स्थान पर था। इसके बाद चीन और अमेरिका का नंबर आता है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76 प्रतिशत दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग और गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बावजूद सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन के दोरान इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता। यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन सड़कों को विस्तृत करने तक ही सीमित है, जिसके कारण कई बार सड़कों और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। ब्लैक स्पॉट वे स्थान होते हैं, जहां सड़क दुर्घटना की आशंका सबसे अधिक रहती है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली 80 प्रतिशत मौतों के लिए वाहन चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं। यह तथ्य देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी की ओर भी इशारा करता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2022

में सङ्क दुर्घटना में लगभग 68 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, जबकि कुल दुर्घटना मौतों में शहरी क्षेत्रों का योगदान 32 फीसद रहा। दुर्घटनाओं और मृत्यु दरों में वोपाहिया वाहनों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही थी यूं तो सङ्क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर काफी प्रयास कर रही है। सङ्क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता बढ़ाने वे लिए सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मैदिया के सभी माध्यमों द्वारा विभिन्न प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्रालय सङ्क सुरक्षा समर्थन के संचालन वे लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी योजना का संचालन कर रहा है। इंडिनियरिंग योजना स्तर पर सङ्क सुरक्षा को सङ्क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। सभी राजमार्ग परियोजनाओं का सभी चरणों में सङ्क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्यकिया गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठने यात्री के लिए एयरबैग के अनिवार्यप्रावधान को लाया किया है। इसके साथ ही कानूनों और प्रवर्तनों में सुधार ढांचागत परिवर्तनों के माध्यम से सङ्कों को सुखिया बनाना और सभी वाहनों में जीवनरक्षक तकनीक उपलब्ध कराना जरूरी किया जाना चाहिए। असल में सङ्क हादसों में कमी लाने के लिए जरूर है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास किया जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश सङ्क



संग्रह की वृत्ति बहिमरुखता का लक्षण है। साधक क्षणजीवी होता है। अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता वह करता है जो आत्मस्थ नहीं होता। वर्तमान में जीना आत्मस्थान का प्रतीक है। एक साधक कल की जरूरत को ध्यान में रखकर संग्रह नहीं करता, पर एक व्यवसायी सात पीढ़ियों के लिए पूरी व्यवस्था जटाने में संलग्न रहता है। यह बात सही है कि साधक अशरीरी नहीं होता, शरीर की अपेक्षाओं को वह गौण नहीं कर सकता; पर दैहिक अपेक्षाओं को लेकर वह मूढ़ नहीं हो सकता। उसका विवेक जागृत रहता है। वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखता है।



अमित बैजनाथ गर्ग

यूं तो अर्थव्यवस्था को रपतार देने वाली सङ्केत देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन आए दिन होने वाले सङ्कक हादसे कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। सङ्कक हादसे भारत जैसे विकासशील देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचआ) ने पिछले साल वैश्वक सङ्कक सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार वैश्वक स्तर पर सङ्कक दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.35 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं, और 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सङ्कक दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतें में से 11 प्रतिशत भारत में होती हैं। सङ्कक दुर्घटनाओं के कारण भारत को होने वाले नुकसान को लेकर विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, 18-45 आयु वर्ग के लोगों की सङ्कक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर सवाधिक 69

मैं उस टीम में खेलना चाहता हूं, जहां मुझे स्वतंत्रता और सम्मान मिले : राहुल

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी बल्लेबाज के पास राहुल ने कहा है कि वह एक ऐसे संघर्षित माहौल में खेलना चाहते हैं, जहां उन्हें सूनी स्वतंत्रता के साथ खेलने का मौका मिले। साथ ही आरसीए में शामिल होने को लेकर भी राहुल ने अपनी गत रसीदी को लखनऊ सुपर जायंस ने राहुल को रिटायर करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है।

कुछ समय पहले ही लखनऊ फैंडेंजी के मालिक संजीव गोयनका ने उन खिलाड़ियों को टीम में रिटायर करने की इच्छा जतावारण हो। जहां आपको पास जाने की मार्गिकात हो गयी है और उस + अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और और लक्षणों से पहले टीम को महत्व दें। क्या इस बात को लिया जाना के लिए उत्तराधिकारी और अब वह मगा नीतार्थी का उत्तराधिकारी कर सकते हैं।

इस साल के जनवार में राहुल ने 12 नवंबर

को स्पर्सोट्स के लिए एक इंटरव्यू में कहा, 'नवंबर नहीं है कि इसी से आगे की सारी चीजें तय हों। मैं बस एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसमें अच्छा जातावारण हो।' जहां आपको पास जाने की मार्गिकात हो गयी है और उस + अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और और लक्षणों से पहले टीम को महत्व दें। क्या इस बात को लिया जाना के लिए उत्तराधिकारी और अब वह मगा नीतार्थी का उत्तराधिकारी कर सकते हैं।

उद्घोष कहा, 'हमने एलएसजी में पहले एंडी प्लायर (हेड कोच) और जीजी (गोपन गंधीर, मैटर्न) के साथ और फिर बिल्डर टीम नए हेड ऑफ चैम्पियन लैंगर के साथ उपर्युक्त के माहौल को बनाने की ओर खिलाड़ियों की साथ खेलना चाहता है। मूले लगता है कि ड्रेसिंग रूम का चालाकरण शामिल है।' लेकिन कपी-कपी आपको खुद के लिए कुछ बेहतर तत्वान्वयन के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है।

राहुल ने 2022 और 2024 में एलएसजी को लैन ऑफ टक फूंका था। जब उसे आईपीएल के लिए जाना और उस बायान में शामिल होना चाहता हूं तो राहुल ने एक बड़े बदलाव के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है।

'आईपीएल में पहले से ही बदल बदल होता है। आप पुजुरात टाइट्स, चेन्नई सुपर किंस और अन्य टीमों को देखते हैं तो उसा साफ़ दिखता है।'



